Statement which *inter-alia* included the commitment of Government to preserve the special Constitutional status of Jammu and Kashmir, its willingness to strengthen the autonomy of the State within the Constitution, keeping in view the aspirations of the people of the entire State, restoration of the nomenclatures of "Wazir-e-Azam" and "Sadar-e-Riyasat" and the plans of the Government to formulate additional financial and development benefits for the State.

Pakistan has continued with the propaganda and disinformation campaign and sponsorship of cross-border terrorism in Jammu and Kashmir. Concerted action is being taken at various levels to counter and expose the designs and attempts of Pakistan.

The various measurs taken by the Government have had a definite positive impact on the situation and the overall atmosphere and mood of the people, and after considering all aspects of the situation, the Government had in November, 1995 recommended to the Election Commission to initiate steps for condcuting elections in the State. However, the Election Commission did not agree with the recommendation. A public interest litigation has been filed against the decision of the Commission and the matter is now sub-judice. The Government has continued to make intensive efforts to further consolidate the situation towards restoration of democratic and representative institutions in the State of Jammu and Kashmir at the earliest. In this process, the Government has held futher discussions with the Election Commission and with the leaders of various political parties and groups from the State. The Government shall continue to follow this approach and pursue its efforts towards restoration of peace and normalcy in the State and there shall be no let up in our efforts in this regard.

एयर इंडिया और इंडियन एयललाइन्स का काम-काज सुधारने हेतु कदम

390. **श्री सत्यप्रकाश मालवीय:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश की दोनों विमान सेवाओं के काम काज में सुधार लाने के लिए पिछले पांच छह वर्षों के दौरान कोई कार्यवाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम रहे हैं;

(ग) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष ने दोनों विमान सेवाओं के काम-काज में सुधार लाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है; यदि हां, तो इसका मूल कारण क्या है; और

(घ) सरकार दोनों विमान सेवाओं के काम-काज में सुधार लाने के लिए समय रहते ही क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार कर रही है और कब से?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क), (ख) और (घ) सरकार एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए लगातार कदम उठाती रही है, जिससे हवाई परिवहन उद्योग में बढ़ती हुई होड़ में इन एयरलाइनों का बेहतर कार्यकरण सुनिश्चित किया जा सके। इन प्रयासों में विभिन्न प्रकार के उपाय सम्मिलित हैं—जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय विमानन अवसरों का विस्तार एयरलाइनों की सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों के रूप में पुनः संरचना, और दोनों एयरलाइनों के समेकित कार्यकरण के लिए किये गये प्रयास शामिल हैं। इन प्रयासों से प्राप्त होने वाले परिणामों की मात्रा को 5-6 वर्षों की लम्बी अवधि में आंकना तो संभव नहीं होगा परन्तु, यह कहा जा सकता है कि एयर इंडिया और इंडियनएयरलाइन्स के अपने उत्पाद और छवि के स्तरोन्यन के प्रयास काफी हद तक सफल हुए हैं और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद दोनों एयरलाइनों विमान परिवहन उद्योग में अपनी अपनी स्थिति बराबर बरकरार बनाए हुए हैं।

(ग) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष द्वारा व्यक्त विचार उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं।